

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 111/2020

No. E.487/O/NA/Vol.V

Kolkata, Dated: 19/11/2020


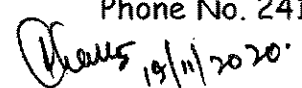
All Concerned

(as per standard list)

Sub: Recovery of Night Duty Allowance (NDA) from Railway employees who have become ineligible to get NDA after issue of Board's letter dated 29/09/2020 (RBE No. 83/2020).

A copy of Ministry of Railway (Railway Board)'s letter bearing no. E(P&A)II-2017/HW-1, dated 06/11/2020 (S.No. PC-VII/160, RBE No. 96/2020) on the above cited subject along with its Hindi version, is enclosed for information and further necessary action. Board's earlier letters dated 08/03/2018 (RBE No. 36/2018) and 29/09/2020 (RBE No. 83/2020) mentioned therein, were circulated under this office serial Nos. 53/2018 and 99/2020

DA: As above


(D. Hansda)
Sr. Personnel Officer/RP
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No. 24112

19/11/2020

Index No. 1053: Recovery of NDA from Railway employees who have become ineligible to get NDA after issue of Board's letter dated 29/09/2020 (RBE No. 83/2020) be deferred until further orders.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VII/160
No.E(P&A)II-2017/HW-1

RBE No. 96/2020
New Delhi, dated 6.11.2020

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.


Sub: Recovery of Night Duty Allowance (NDA) from Railway employees who have become ineligible to get NDA after issue of Board's letter dated 29.09.2020 (RBE No. 83/2020).

Please refer Board's letter of even number dated 08.03.2018 (RBE No. 36/2018) whereby the revised rates of NDA for 7th CPC period effective from 01.07.2017 were conveyed to zonal Railways. Subsequent to issue of DoP&T's O.M. dated 13.07.2020 on Night Duty Allowance, further instructions issued vide Board's letter dated 29.09.2020 (RBE No. 83/2020) prescribing Rs. 43600/- as ceiling of Basic Pay for entitlement of NDA. Federations have represented against the decision of ceiling-limit of pay and demanded for its review. While considering Federations' demand, Board have decided to refer the matter to DoP&T for clarification and, in the interim, recovery of NDA from Railway employees who have become ineligible for the same after issue of Board's letter dated 29.09.2020 be deferred until further orders.

Railways are accordingly, advised to defer recovery against NDA until further orders.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version is enclosed.



(N. P. Singh)

Jt. Director, Estt.(P&A)
Railway Board

No. E(P&A)II-2017/HW-1

New Delhi, dated 6.11.2020

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.



For Member(Finance), Railway Board

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

क्र.सं. पीसी-VII/60

सं.ई(पी एण्ड ए)II/2017/एचडब्ल्यू-1

आरबीई सं. 96 /2020

नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2020

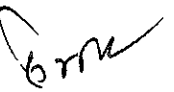
महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: रेल कर्मचारियों, जो बोर्ड के दिनांक 29.09.2020(आरबीई सं. 83/2020) का पत्र जारी होने के बाद रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, से रात्रि ड्यूटी भत्ता (एनडीए) वसूल करना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 08.03.2018(आरबीई सं.36/2018) के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा 01.07.2017 से लागू सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते की संशोधित दरों के बारे में क्षेत्रीय रेलों को सूचित किया गया था। तदुपरांत रात्रि ड्यूटी भत्ता के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.07.2020 का कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद, बोर्ड के दिनांक 29.09.2020 (आरबीई सं. 83/2020) के पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें रात्रि ड्यूटी भत्ता का पात्र होने के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा ₹43600/- निर्धारित की गई थी। फेडरेशनों ने वेतन की अधिकतम सीमा के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और इसकी समीक्षा करने की मांग की है। फेडरेशनों की मांग पर विचार करते हुए, बोर्ड ने इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया है और इस दौरान, रेलवे ने विनिश्चय किया है कि उन रेल कर्मचारियों, जो बोर्ड के दिनांक 29.09.2020 का पत्र जारी होने के बाद रात्रि ड्यूटी भत्ते के पात्र नहीं हैं, से रात्रि ड्यूटी भत्ते की वसूली अगले आदेशों तक स्थगित की जाए।

तदनुसार, रेलों को सूचित किया जाता है कि अगले आदेशों तक रात्रि ड्यूटी भत्ते के तहत वसूली स्थगित की जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक स्थापना(वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एण्ड ए)II/2017/एचडब्ल्यू-1

नई दिल्ली, दिनांक 06.11.2020

प्रतिलिपि अग्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते सदस्य(वित्त), रेलवे बोर्ड